

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 2 जनवरी, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/111-85/295.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० गुडईयर इण्डिया लि०, वल्लवगढ़, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्रमिक श्री कृष्ण लाल को 10 दिन के निलम्बित समय की बिना वेतन की दी गई सजा उचित है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/307.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रावल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बहाधुरगढ़ के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक प्राधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

- (1) क्या संस्था के श्रमिक प्रति मास 60 रुपये क्वाटर अलाऊंस के हकदार बनते हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?
- (2) क्या संस्था के श्रमिक ऋतु के अनुसार दो वर्दी व दो जूतों की जोड़ी लेने के पात्र बनते हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?
- (3) क्या संस्था के श्रमिक वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 के प्रोडक्शन बोनस के हकदार बनते हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?

कुलवन्त सिंह,

वितायुक्त एवं सचिव ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 24 दिसम्बर, 1985

सं० ओ० वि०/हिसार/69-85/52051.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) हरियाणा राज्य सिचाई विभाग, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता हरियाणा, राज्य लघु सिचाई निगम, डिविजन नं० 2, फतेहाबाद, के श्रमिक श्री सतपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री सतपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?